RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : सोमवार 24 जून 2024 वर्ष 06 अंक 67 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

पालघर जिले में बंदरगाह का रास्ता साफ

Page - 4

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

मुंबई जा रही एमएसआरटीसी की बस पेड़ से टकराई, 25 यात्री घायल

पुणे : महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस के पेड़ से टकराने से करीब 25 यात्री घायल हो गए। यह घटना यवत गांव के सहजपुर फाटा में हुई, जब बस पंढरपुर (सोलापुर जिले में) से मुंबई की ओर जा रही थी।तीन से चार यात्रियों को कुछ गंभीर चोटें भी आईं।यवत पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक नारायण देशमुख ने कहा, ''यवत गांव में सहजपुर फाटा के पास एक राज्य परिवहन बस के पेड़ से टकराने से करीब 25 यात्री घायल हो गए। तीन से चार यात्रियों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है।

''दुर्घटना के पीछे का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। पीटीआई ने देशमुख के हवाले से कहा, ''रास्ते में एक ट्रक अचानक रुका और टक्कर से बचने के लिए बस सड़क से उतर गई और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई।''घायलों को लोनी कालभोर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बेघरों को घर देगी शिंदे सरकार

12,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना

मुंबई : एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ''सबका साथ, सबका विकास'' नारे को तेजी से लागू कर रही है। हाल ही में, उन्होंने ओबीसी श्रेणी के बेघर लाभार्थियों के लिए मोदी आवास योजना शुरू की। इस पहल का लक्ष्य पूरे राज्य में 15 लाख से अधिक घर बनाना है। नागपुर जिले में इस योजना के तहत 6,739 घरों को मंजूरी दी गई है। अब तक 651 घर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिससे कई बेघर परिवारों को आश्रय मिला है। राज्य सरकार इस योजना पर करीब 12,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को लक्षित करता है जो प्रधानमंत्री घरकुल योजना से लाभ पाने से चूक गए थे।

योजना के पहले वर्ष, 2023-24 में नागपुर जिले के लिए 6,747 घरों का लक्ष्य रखा गया था। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) को इन मकानों के लिए प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से 6,739 मकानों को मंजूरी दे दी गई है। शेष आठ मकानों के लिए मंजूरी प्रक्रिया जारी है। बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और रमाई एवं शबरी योजना जैसी अन्य योजनाओं से भी लाभ मिला है। शिंदे सरकार की इन योजनाओं से कई जरूरतमंदों को आश्रय प्रदान किया जा रहा है। ये भी पढ़ें:- शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट क्या है?

महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया क्यों है ये जरूरी मोदी आवास योजना महाराष्ट्र में बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों और ओबीसी लाभार्थियों पर ध्यान केंद्रित करके, इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की विकास यात्रा में कोई भी पीछे न छूट जाए।

मुंबईकरों को बीएमसी एक और झटका; 8% वृद्धि दर का प्रस्ताव

मुंबई : पानी कटौती की समस्या से जूझ रहे मुंबईकरों को बीएमसी एक और झटका देने वाली है। बीएमसी मुंबईकरों का पानी महंगा करने की तैयारी कर रही है। एक अधिकारी ने बताया कि पानी की दर में करीब 8% तक की वृद्धि हो सकती है। इससे पीने का पानी 25 पैसे से 6 रुपये तक महंगा हो सकता है। अधिकारी ने बताया कि बढ़ी हुई दर 16 जून से लागू होंगी। बता दें कि 2023 में भी बीएमसी ने 8% वृद्धि दर का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन वह लागू नहीं हो सका था। तब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हस्तक्षेप करते हुए प्रस्ताव को रद्द करने का आदेश दिया था।

बीएमसी का नियम क्या कहता है

बीएमसी अधिकारी ने बताया कि यह बीएमसी का कानून है कि हर साल पानी के दाम में 8% की वृद्धि हो जाएगी और नई वृद्धि दर 16 जून से लागू मानी जाएगी। लेकिन उसके लिए बीएमसी को नया प्रस्ताव तैयार कर कमिश्नर की मंजूरी जरूरी होती है।बीएमसी ने 2012 में यह नियम बनाया था कि हर साल पानी की दर में अधिकतम 8% की वृद्धि होगी और यह हर साल 16 जून से लागू होगा। बीएमसी हर तीसरे महीने में पानी का बिल उपभोक्ताओं को भेजती है। नए बिल में बकाया रकम को एड कर दिया जाएगा।

पानी महंगा होने का यह कारण

बीएमसी मुंबईकरों को सात झीलों से रोज 3850 एमएलडी पानी की आपूर्ति करती है। यह पानी ठाणे, पालघर और नासिक जिलों से करीब 100 किमी लंबी पाइप लाइन से होती है। बीएमसी का कहना है कि पानी आपूर्ति के लिए प्रशासनिक खर्च के साथ ऊर्जा और पानी के शुद्धिकरण का खर्च बढ़ गया है।

सब- इंस्पेक्टर के खिलाफ महिला कॉन्सटेबल से रेप का मामला दर्ज; 19 लाख रुपये भी ऐंठे!

ठाणे: महाराष्ट्र के नवी मुंबई इलाके में एक बेहद शर्मसार करने वाला मामले सामने आया है. 32 साल के एक पुलिस सब- इंस्पेक्टर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि यह पुलिस सब-इंस्पेक्टर शादीशुदा महिला कॉन्स्टेबल का लगातार न सिर्फ रेप कर रहा था बल्कि उसे खुद से शादी करने, अपने पति को छोड़ देने और पैसे ऐंठने का काम भी कर रहा था.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस सब-इंस्पेक्टर ने ये कुकर्म साल 2020 और जुलाई 2022 के बीच सानपाड़ा इलाके में किए थे. अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने 26 साल की पीड़ित महिला से दोस्ती की, दोनों मुंबई पुलिस से जुड़े थे और उससे शादी करने का वादा करने के बाद सानपाड़ा के एक फ्लैट में कई बार उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया. पुलिस ने कहा कि उसने समय-समय पर किसी न किसी बहाने से वह पीड़ित महिला से पैसे भी ऐंठता रहा. अब तक वह महिला से 19 लाख रुपये भी ले चुका है जिसमें से केवल 14.61 लाख रुपये ही लौटाए हैं. सानपाड़ा पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने महिला का पीछा भी किया और उससे अपने पति को छोड़ने के लिए कहा, ऐसा न करने पर उसने उसे जान से मारने की धमकी दी.

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, शुरूआत में मुंबई के पंत नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 376 (2) (एन) (बार-बार बलात्कार), 354 (ए) (यौन उत्पीड़न), 354 (डी) (पीछा करना), 506 (2) (आपराधिक धमकी) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत 'जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी. उन्होंने कहा कि इसे आगे की जांच के लिए सानपाड़ा पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया जहां शनिवार को मामला दर्ज किया गया.

संपादकीय...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

प्रकृति से छेड़छाड़

मानसून के आगमन के बीच हम सब इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि इस बार कितनी अधिक गर्मी पड़ रही है और लू का कहर किस तरह जानलेवा सिद्ध हुआ। गर्मी और लू के प्रकोप का सामना दुनिया के अन्य देशों को भी करना पड़ रहा है। निःसंदेह मानसून राहत देगा, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मौसम में अप्रत्याशित बदलाव खतरे की एक घंटी है। पर्यावरणविदों के अध्ययनों के आधार पर यह पहले ही साफ हो चुका था कि 2024 में गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है। पर्यावरणविदों के अनुसार इस वर्ष एल नीनो का असर होगा और फिर उसके तत्काल बाद ला नीना का भी। एल नीनो गर्मी को बढ़ाएगा तो ला नीना शीतकालीन परिस्थितियों को और गंभीर कर देगा।

एक अध्ययन के अनुसार, 2023 में एल नीनो ने पिछले साल जुलाई को अत्यधिक गर्म किया। वैसे ही हालात इस साल जून के आसपास दिखे। अपने देश में देखें तो दिल्ली में तापक्रम 50 के आसपास पहुंच गया। अन्य शहरों में भी इसी के आसपास तामपान पहुंचा। पहाड़ों में भी गर्मी बढ़ी तो जैसलमेर में तापमान ने 55 का आंकड़ा छू लिया। अब यह भी स्पष्ट हो चुका है कि 2024 तापक्रम वृद्धि को लेकर अच्छा नहीं कहा जा सकेगा। 2016 से 2019 के तीन साल के लंबे दौर के बाद 2023 में ही एल नीनो दूसरी बार आया और दिसंबर 2023 में यह अपने चरम पर था। समुद्री वायुमंडल के हालात बिगड़ने के कारण अगस्त 2024 में यह और प्रभाव डालेगा। इसके तुरंत बाद ला नीना के प्रभाव की आशंका है।

इस बार जापान और मेक्सिको में बसंत से पहले ही फूल खिलने लगे थे। इसी तरह यूरोप में फरवरी-मार्च में ही हिमखंड पिघलने लगे। इसी समय अमेरिका के टेक्सास में तापक्रम 38 के पार चला गया था। भारत में भी गर्मी के जल्दी आने से वनों की आग ज्यादा घातक हो गई। जापान से मेक्सिको तक तापक्रम की वृद्धि पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ रही है और परिस्थितिकी में कुछ बड़े मूलभूत परिवर्तन आ रहे हैं। अपने देश में जनवरी- फरवरी कुछ इस तरह से बीते, जैसे बसंत आ गया हो। बीते जाड़े में भी ठंड का अधिक प्रभाव नहीं था।

वास्तव में लगातार लंबे समय से मौसम के व्यवहार का सही अनुमान नहीं लगाया जा पा रहा है। देश में बसंत वाली गर्मी पहले ही आ गई थी और उसने वनाग्नि जैसे दावानल के लिए दरवाजे खोल दिए। यह भी संज्ञान में लेना जरुरी है कि पश्चिमी विक्षोभ, जो पहले नवंबर-दिसंबर के महीने में आता था, इस बार फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह में ही दिखाई दे गया। यह एक बहुत बड़ा लक्षण है कि अब मौसम का समयानुसार प्रभाव नहीं रहा। मौसम के अनुकूल न होने के कारण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर

editor@rokthoklekhaninews.com
+91 99877 75650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) का रणनीति पर पुर्नविचार

मुंबईः लोकसभा चुनाव 2024 में एनसीपी (शरद गुट) ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने दस में से आठ सीटों पर जीत हासिल की, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को चार सीटों में से केवल एक सीट पर जीत मिली है.

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है. ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रही है.

दरअसल, एनसीपी (शरद पवार गुट) के सुप्रीमो शरद पवार ने पुणे शहर और जिले के पार्टी पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को एक बैठक की. इस बैठक में विधायकों और नवनिर्वाचित सांसदों के साथ एक सत्र आयोजित किया गया.

पहली बैठक में शामिल हुए पुणे शहर के एनसीपी (शरद पवार गुट) प्रमुख प्रशांत जगताप ने खुलासा किया

कि शरद पवार ने लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या कम करने को शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस के साथ गठबंधन को बरकरार रखने के लिए एक आवश्यक समझौता बताया. जगताप ने संकेत दिया कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में तस्वीर अलग होगी.

इसके अलावा दूसरी बैठक में शरद पवार ने सांसदों और विधायकों से विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसने का आग्रह किया. उन्होंने पुणे, बारामती, मावल और शिरुर समेत प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी परिदृश्य की समीक्षा की.

इस बीच, राज्य एनसीपी (शरद पवार गुट) प्रमुख जयंत पाटिल ने प्रेस को बताया कि पार्टी ने अभी तक एमवीए के साथ सीट बंटवारे की बातचीत के लिए अपनी मांगों को अंतिम रूप नहीं दिया है.

एनसीपी (शरद पवार गुट) के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने एमवीए की एकता पर जोर दिया. उन्होंने जोर देकर कहा, ''एमवीए में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है, यहां सभी बराबर हैं.''

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनसीपी (शरद गुट) ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने दस में से आठ सीटों पर जीत हासिल की, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को चार सीटों में से केवल एक सीट पर जीत मिली है.

शिव ट्रांसपोर्ट सेना महासचिव की कार दुर्घटनाग्रस्त

पनवेलः शिव परिवहन सेना के राज्य महासचिव महेश केदारी 23 जून को सुबह मुंबई जा रहे थे, तभी उनकी कार को एक टेम्पो ने टक्कर मार दी. इस

दुर्घटना में केदारी मामूली रूप से घायल हो गये। प्राप्त जानकारी के अनुसार महेश केदारी आज सुबह अपनी मारुति ब्रेजा कार क्र. एमएच 14 एचके 0679 से मुंबई के लिए रवाना हुआ था। नई मुंबई में घनसोली के पास एक टेम्पो नं. एमएच 04 केएक्स 7584 को जोरदार टक्कर लगी और वह पलट गया। इस दुर्घटना में केदारी को मामूली चोटें आईं और कार क्षतिग्रस्त हो गई।

पनवेल शहर के सेंट फ्रांसिस न्यू चर्च में चोरी

पनवेलः पनवेल शहर के लाइन अली इलाके में स्थित सेंट फ्रांसिस न्यू चर्च में चोरी हो गई थी. चर्च की अलमारी से पांच हजार नकदी की चोरी के बाद श्रद्धालुओं ने आक्रोश जताया है. चर्च के प्रबंधक द्वारा पनवेल शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने इलाके का निरीक्षण किया.

विधानसभा चुनाव जीतने के लिए दलितों और अल्पसंख्यकों को महायुति के पाले में लाना होगा - रामदास आठवले

मुंबईः आरपीआई नेता रामदास आठवले ने कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए दलितों और अल्पसंख्यकों को महायुति के पाले में लाना होगा। उन्होंने कहा कि वह महायुति नेताओं की बैठक में यह बात रखेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने शनिवार को महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को सलाह दी कि विधानसभा चुनाव में जीत के लिए उसे दलितों और अल्पसंख्यकों को अपने साथ लेने की जरूरत है। उन्होंने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) अक्तूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आठ से दस सीट की मांग करेगी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट हैं।

'विधानपरिषद चुनाव में भी करेंगे एक सीट की मांग'

सत्तारूढ़ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (रांकपा) शामिल है। आठवले ने कहा कि हम अगले महीने वाले विधानपरिषद चुनाव में एक सीट की भी मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल के प्रस्तावित विस्तार में उन्हें एक मंत्री पद मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह उनकी मांग पर विचार किया जाएगा। आठवले ने कहा कि वह चाहते थे कि उनकी पार्टी शिरणी और शोलापुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा ने उनके अनुरोध को नहीं माना। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें (भाजपा नीत राजग को) उम्मीद थी कि महाराष्ट्र की 40 सीट जीतेंगे, लेकिन 17 ही जीती। उन्होंने आम चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के खराब प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि विपक्ष के इस दावे से दलित मतदाता भ्रमित हुए कि अगर भाजपा ने 400 से अधिक सीट जीतीं तो वह संविधान बदल देगी।उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के महा विकास आघाड़ी (एमवीए) और महायुति के मत प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने कहा, ''विधानसभा चुनाव जीतने के लिए दलितों और अल्पसंख्यकों को महायुति के पाले में लाना होगा। मैं महायुति नेताओं की बैठक में यह बात रखूंगा।'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर एकजुट रहे तो सत्तारूढ़ गठबंधन चुनाव जीत सकता है।

ओबीसी कार्यकर्ताओं का अनशन सरकारी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद समाप्त

मुंबई : महाराष्ट्र में दस दिनों से अनशन पर बैठे दो ओबीसी कार्यकर्ताओं का अनशन सरकारी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद समाप्त किया गया। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि अनशन फिर से शुरू किया जा सकता है, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। दरअसल 13 जून से दो अन्य पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे। इनसे पहले मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे जालना में मराठा आरक्षण को लेकर अनशन कर रहे थे। अनशन पर ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हेके और नवनाथ वाघमारे बैठे थे। शनिवार को महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने अनशन समाप्त करने के बाद कहा कि हम अनशन अस्थायी रूप से स्थगित कर रहे हैं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम इसे फिर से शुरू करेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार की मसौदा अधिसूचना पर आपत्तियों के बारे में एक ''श्वेत पत्र'' जारी किया जाना चाहिए। जिसमें 'ऋषि-सोयारे' या मराठों के रिश्तेदारों को कुनबी प्रमाण पत्र देने की बात कही गई है, जिन्होंने पहले ही अपनी कुनबी स्थिति स्थापित कर ली है। बता दें कि कुनबी एक कृषि प्रधान ओबीसी समुदाय है। 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में मंत्री छगन भुजबल, अतुल सावे, गिरीश महाजन, धनंजय मुंडे, उदय सामंत और विधान परिषद सदस्य गोपीचंद पडलकर शामिल थे। खुद एक प्रमुख ओबीसी नेता भुजबल ने बताया कि 29 जून को कोटा मुद्दे पर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हेक और वाघमारे को आमंत्रित किया गया था। मुंबई में शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा बुलाई गई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ओबीसी कोटा को कुछ नहीं किया जाएगा। कुछ मराठों को जारी किए गए फर्जी कुनबी प्रमाण पत्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि मनोज जारंगे और उनके सहयोगी मराठों के लिए कुनबी जाति प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं, इस मांग का ओबीसी नेता विरोध कर रहे हैं। भुजबल ने मराठा समुदाय से ओबीसी दर्जे का दावा करने के बजाय सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अलग से आरक्षण की मांग करने का आग्रह किया। वरिष्ठ एनसीपी नेता का कहना है कि ''हमारा हिस्सा मत छीनिए।'' उन्होंने कहा कि आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए है, गरीबी उन्मूलन के लिए नहीं।

जरांगे विधानसभा चुनाव में दे सकते हैं बड़ा झटका

मुंबई : तीन दलों की मिली-जुली महाराष्ट्र सरकार आरक्षण के भंवर जाल में फंसती जा रही है। उसे समस्या का हल नहीं दिखाई दे रहा है। सत्ताधारी दलों के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर आरक्षण के मसले को हल नहीं किया गया, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लोकसभा से भी डरावने नतीजे आ सकते हैं। हालांकि आरक्षण के भंवर जाल से निकलने के लिए सत्ताधारी दल नित नए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हर प्रयोग औंधे मुंह गिर रहा है। मराठा आरक्षण का चेहरा बने मनोज जरांगे पाटील ने सत्ताधारी दल को बुरी तरह से घेर लिया है। माना जा रहा है कि हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पंकजा मुंडे, रावसाहेब दानवे जैसे दिग्गजों का जरांगे पाटील ने विकेट ले लिया। नांदेड में अशोक चव्हाण चारों खाने चित हो गए। सन 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां अकेले बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं इस बार 9 सीटों तक सिमट गई। जरांगे पाटील पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो सरकार को यहां तक चेता दिया है कि मराठा आरक्षण को हल नहीं किया, तो वे विधानसभा की सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उनके उम्मीदवार जीते या हारे इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लोग सत्ताधारी दलों के उम्मीदवार को जरूर गिरा देंगे। जरांगे को मनाने के लिए सरकार हर तरह से हथकंडे अपना रही है, लेकिन जरांगे टस से मस नहीं हो रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन कहते हैं कि जहां तक उनकी जानकारी है कि जिस तरह के आरक्षण की मांग जरांगे पाटील कर रहे हैं, वह संभव नहीं है, फिर भी अगर कोई व्यावहारिक समाधान है, तो सरकार इसे आगे बढ़ाएगी। इस पर जरांगे कहते हैं कि वो अपने इस रुख पर अडिग हैं कि मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आरक्षण मिलना चाहिए।

ओबीसी अड़े

इससे पहले कि मराठा आरक्षण के लिए अड़े जरांगे पाटील को सरकर मना पाती, ओबीसी आरक्षण का मामला भी गरमा गया है। जालना में ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे पिछले 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्हें मनाने के लिए कैबिनेट मंत्री गए। बाद में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी एक प्रतिनिधि मिलने गया। वहां से शिंदे से

मोबाइल पर बात कराया गया। इनकी मांग पर ही शिंदे ने तत्काल संबंधित लोगों की बैठक बुलाई। बैठक में ओबीसी नेताओं ने अपनी ही सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। अपनी नाराजगी प्रकट की। ताने मारे कि मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे जरांगे पाटील को मनाने के लिए पूरी सरकार उतर गई, लेकिन ओबीसी समाज का कोई अनशन पर बैठा, तो उसे किसी ने नहीं पूछा। उन तक पहुंचने में सरकार को एक सप्ताह लग गए। ओबीसी मसले को लेकर राज्य में एक बार फिर तनाव की स्थिति है। राज्य के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

धनगर मांगे एसटी आरक्षण

सन 2014 के विधानसभा चुनाव प्रचार में देवेंद्र फडणवीस ने वादा किया था कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी तो पहली ही कैबिनेट की बैठक में धनगर समाज की मांग को मंजूर करेंगे। धनगर की मांग थी कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए, ताकि एसटी को मिल रही सुविधाएं उन्हें मिल सकें। लेकिन उनकी मांग आज तक पूरी नहीं हुई। इस पर टाटा इंस्टीट्यूट यानी टिस की रिपोर्ट है कि धनगर को एसटी में शामिल नहीं किया जा सकता। हालांकि, धनगर समाज को सरकार साढ़े तीन प्रतिशत आरक्षण दे रही है, लेकिन धनगर नेताओं की मांग है कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए। यह मामला भी अब जोर पकड़ने लगा है।

महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण

सन 2014 में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले पृथ्वीराज चव्हाण सरकार ने मराठों को 16 और मुस्लिमों को 5 % आरक्षण मंजूर किया था। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। अबकी केंद्र की मोदी सरकार में चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए हैं। उन्होंने अपने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समाज को 4% आरक्षण का समर्थन किया है। ऐसे में महाराष्ट्र में फिर से मांग उठने लगी है कि महाराष्ट्र में भी मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। पूछे जा रहे हैं कि बीजेपी की सहयोगी दल चंद्रबाबू अपने राज्य में मुसलमानों को 4 % आरक्षण दे रही, तो महाराष्ट्र की वही बीजेपी सरकार मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं दे रही है। यह मामला भी गरमाने की आशंका है।

कैसे सुलझेगा मामला

महाराष्ट्र में आरक्षण 72 प्रतिशत तक जा पहुंच है। धनगर, गडरिया समाज को 3.50% आरक्षण अलग से मिला रहा है, लेकिन उनकी मांग है कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए। इसी तरह से जरांगे पाटील की मांग है कि उनके कुनबी मराठा को ओबीसी में शामिल किया जाए, जबकि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके को अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है। ओबीसी कुनबी मराठों को शामिल करने का यह कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि पहले से ही ओबीसी में 350 जातियां शामिल हैं। ऐसे में कुनबी मराठा को शामिल करने से उन्हें मिल रहा आरक्षण प्रभावित होगा। मुस्लिम समाज अब तर्क दे रहे हैं कि बीजेपी की सहयोगी टीडीपी आंध्र प्रदेश में 4 प्रतिशत आरक्षण दे रही है, तो महाराष्ट्र सरकार को किस बात को एलर्जी है? सभी उलझा हुआ है और उलझन के धागे सत्ताधारी दल को नहीं मिल रहा है।

किसकी क्या मांग है:

- धनगर समाज के नेताओं की मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाए, ताकि उन्हें दी जा रही सुविधाएं धनगर समाज को मिल सके।

-मनोज जरांगे पाटील की मांग है कि उन्हें कुनबी मराठा ओबीसी में शामिल किए जाएं, क्योंकि 1884 के हैदराबाद और बॉम्बे गजट में उन्हें ओबीसी माना गया है, लेकिन सरकार हमें ओबीसी नहीं मानती।

- ओबीसी कहते हैं कि ओबीसी में पहले से ही करीब 350 जातियों को शामिल किया गया है। अब मराठों को शामिल करने से उनका आरक्षण प्रभावित होगा, इसलिए मराठों को ओबीसी में शामिल नहीं किया जाए।

विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटका; पूर्व केंद्रीय मंत्री ने छोड़ी पार्टी

नांदेड़। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांत पाटिल ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद कहा कि मैंने पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है। मैं पार्टी की आभारी हूं।

सीट बंटवारे के दौरान हिंगोली सीट एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के लिए छोड़ दी गई थी। आम चुनाव के दौरान भाजपा ने उन्हें हदगांव हिमायतनगर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रमुख की जिम्मेदारी दी थी। शिवसेना हिंगोली सीट उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट से हार गई थी। पाटिल ने चार बार सांसद और एक बार विधायक के रूप में हिंगोली-नांदेड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। वह संप्रग सरकार के दौरान ग्रामीण विकास और संसदीय मामलों की राज्य मंत्री थीं।

नीट पेपर लीक में पुलिस ने दो अध्यापकों से की पूछताछ

मुंबईः नीट पेपर लीक का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। बिहार पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। अब नीट पेपर लीक का कनेक्शन महाराष्ट्र में भी मिला है। पुलिस ने दो अध्यापकों से पेपर लीक मामले में पूछताछ की है। जिन अध्यापकों से पूछताछ हुई है, उन्हें नांदेड़ की आंतकरोधी स्कवॉड ने शक के आधार पर पकड़ा।

दोनों अध्यापकों पर पेपर लीक में शामिल होने का संदेह

पुलिस को शक है कि ये दोनों अध्यापक नीट पेपर लीक मामले में शामिल हो सकते हैं। दोनों महाराष्ट्र के जिला परिषद स्कूलों में पढ़ाते हैं। साथ ही दोनों लातूर में निजी कोचिंग सेंटर भी संचालित करते हैं। पुलिस ने दोनों से कई घंटे तक पूछताछ की और फिर जाने दिया।

पुलिस ने दोनों को जरूरत पड़ने पर फिर से पूछताछ के लिए पेश होने का भी निर्देश दिया है। देश में इन दिनों नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर हंगामा चल रहा है और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जांच की जा रही है। दरअसल नीट परीक्षा में पेपर लीक होने का शक है। वहीं यूजीसी नेट की परीक्षा सरकार ने रद्द कर दी है। सरकार का कहना है कि यूजीसी नेट का पेपर डार्कनेट पर लीक हो गया था, जिसके चलते परीक्षा के अगले दिन ही परीक्षा को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया।

सरकार ने नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी

विपक्ष और सामाजिक संगठन नीट यूजी का पेपर लीक होने का आरोप लगा रहे हैं और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। बिहार पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया कि परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। पुलिस अब सॉल्वर गैंग के लोगों से भी पूछताछ कर रही है।

शेयर ट्रेडिंग घोटाले का शिकार ; 94 लाख रुपये का नुकसान

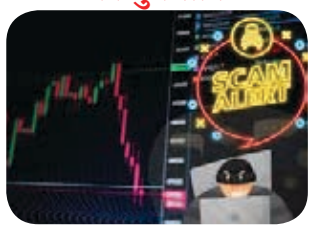

ठाणेः जिले के एक 48 वर्षीय व्यक्ति को शेयर ट्रेडिंग घोटाले का शिकार होने के बाद लगभग 94 लाख रुपये का नुकसान हुआ. कल्याण इलाके में रहने वाले एक शख्स के साथ 9 अप्रैल से 21 मई के बीच ठगी हुई. इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा कि उसे 'द वैल्यू टीम ए13' नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला, जिसमें कई सदस्य खुद को विशेषज्ञ बताते थे। वो लोग शेयर मार्केट से पैसे कमाने के टिप्स दे रहे थे. इस बीच, उन्होंने एप्लिकेशन का उपयोग करके लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित किया। पीड़ित ने उनके द्वारा सुझाए गए आवेदन के माध्यम से कुल 93.6 लाख रुपये का निवेश किया, लेकिन बदले में एक पैसा भी नहीं मिला। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस साक्ष्य जुटाकर आरोपियों की तलाश कर रही है।

महिला और उसकी बेटी कई महीनों से हाईवे के किनारे रह रही थी; महीनों बाद अपने परिजन से मिली

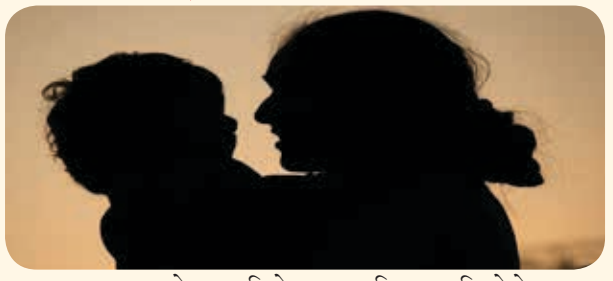

लातूर : महाराष्ट्र के लातूर जिले में पति और बेटे की मौत के सदमे से मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुकी महिला महीनों बाद अपने परिजनों से मिली। महिला और उसकी बेटी कई महीनों से हाईवे के किनारे रह रही थी।

महाराष्ट्र के लातूर जिले में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला और उसकी 4 वर्षीय बेटी को कुछ युवकों ने उसके परिजनों से मिलवाया। महिला काफी महीनों से हाईवे के किनारे अपनी बेटी के साथ रह रही थी। महिला और उसकी बच्ची अपने परिजनों से मिलकर बेहद खुश हैं।

दरअसल फरवरी में औरद-शाहजानी रोड पर एक महिला और बच्ची को देखा गया था। महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ लग रही थी तो लोगों ने एक एनजीओ को सूचना दी, जो कि इस तरह के लोगों के लिए काम करते हैं। धर्म से उत्तरदायित्व के पदाधिकारी राहुल पाटिल चाकुरकर ने बताया कि सूचना मिलने के बाद जब हम उस जगह पर पहुंचे तो हमने देखा कि महिला शिरशी हंगरगा गांव में एक जगह बैठी थी। वहां से तकरीबन 100 मीटर दूर उसका का बेटा एक कुएं में डूब गया था। उसके पति की भी कुछ देर बाद मौत हो गई थी। इस सब के चलते उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो गई थी।

एनजीओ के लोग महिला को बुलढाणा जिले के वरवंद में दिव्य सेवा आवासीय पुनर्वास केंद्र लेकर पहुंचे, वहां उसकी देखभाल की गई। उन्होंने बताया कि ''केंद्र में कुछ महीनों तक उपचार के बाद महिला और उसकी बेटी हाल ही में निलंगा तहसील में अपने रिश्तेदारों से मिल गईं। उसका दूसरा बेटा, जिसने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है और एक होटल में काम करता है। उसकी बेटी अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हैं।''

36 लाख के इनामी नक्सली ने पत्नी के साथ किया सरेंडर, देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद

गढ़चिरौली : अधिकारियों ने बताया कि गिरिधर के खिलाफ 179 मामले दर्ज हैं। जिनमें से 86 मुठभेड़ और 15 आगजनी के हैं। उसकी पत्नी संगीता पर 17 मामले दर्ज हैं। उसके सिर पर 16 लाख रुपये का इनाम था।

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में कुख्यात नक्सली नांगसू तुमरेती उर्फ गिरिधर ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजदगी में अपनी पत्नी के साथ शनिवार को आत्मसमर्पण किया। उसके नाम पर 170 से अधिक मामल दर्ज हैं। उसके सिर पर 25 लाख रुपये का भी इनाम रखा गया था। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि गिरिधर की पत्नी संगीता उसेंडी उर्फ ललिता पर 17 मामले दर्ज हैं। उसके सिर पर 16 लाख रुपये

का इनाम रखा गया था। उन्होंने बताया कि गिरिधर 1996 में एटापल्ली दलम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) में शामिल हुआ था। वह गढ़चिरौली में संगठन की गतिविधियों का प्रमुख था। उन्होंने आगे बताया कि गिरिधर के खिलाफ 179 मामले दर्ज हैं। जिनमें से 86 मुठभेड़ और 15 आगजनी के हैं। उसकी पत्नी संगीता पर 17 मामले दर्ज हैं। उसके सिर पर 16 लाख रुपये का इनाम था। आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार से गिरिधर को 15 लाख रुपये और ललिता को 8.50 लाख रुपये मिलेंगे। फडणवीस ने कहा, नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस और प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिली है। माओवाद की रीढ़ माने जाने वाले गिरिधर और उसकी पत्नी दोनों ने आज आत्मसमर्पण कर दिया है। गिरिधर पर 25 लाख रुपये और उसकी पत्नी पर 16 लाख रुपये का इनाम था।

नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस-प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी: फडणवीस

पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गिरिधर के आत्मसमर्पण से गढ़चिरौली में नक्सल आंदोलन की कमर टूट गई है। उन्होंने नक्सली समस्या को खत्म करने और नक्सलियों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए गढ़चिरौली पुलिस के प्रयासों की सराहना की।

उन्हें गढ़चिरौली में नक्सली गतिविधियों के प्रमुख के रूप में देखा जाता था। आज गढ़चिरौली में हमारे सी-60 बल ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि या तो माओवादियों को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा या परिणाम भुगतना पड़ेगा।

उन्होंने कहा, बीते चार वर्षों में गढ़चिरौली में एक भी व्यक्ति नक्सली गतिविधियों में शामिल नहीं हुआ है। यह अब कोई भर्ती नहीं है। पुलिस उन्हें दूरदराज के इलाकों में ले जा रही है। गढ़चिरौली को महाराष्ट्र का आखिरी छोर माना जाता था। लेकिन उस चीज को बदल दिया है। अब हम इसे महाराष्ट्र के पहले जिले के रूप में देखते हैं।

घोड़बंदर किले के तहखाने में मिला छिपा हुआ कमरा; राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा

भायंदर :- ऐतिहासिक घोड़बंदर किले के सौंदर्यीकरण कार्य के दौरान तहखाने में एक छिपा हुआ कमरा मिला है, जिसके चलते पुरातत्व विभाग ने किले का दौरा किया और इसका निरीक्षण किया। मीरा-भिंदर शहर में एक ऐतिहासिक घोड़बंदर किला है। यह किला पुरातत्व विभाग के साथ पंजीकृत है। लेकिन पिछले कई वर्षों से यह किला खराब होने लगा है, इसलिए नगर पालिका ने राज्य सरकार से घोड़बंदर किले को देने का अनुरोध किया 'महाराष्ट्र वैभव- राज्य संरक्षित स्मारक योजना' के तहत इसे वर्ष 2019 में सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। इसके बाद किले की विकास योजना तैयार की गई है और

पुरातत्व की मदद से किले का संरक्षण कार्य किया गया है। विभाग ने कहा कि किले का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और आसपास के क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। इस दौरान श्रमिकों को कुछ असामान्य दीवारों वाला एक तहखाना नजर आया। इसकी सूचना शुरूआत में स्थानीय नागरिकों ने राज्य पुरातत्व विभाग को दी एक सबवे बनने के लिए, लेकिन पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों ने किले का दौरा किया और स्पष्ट किया कि यह एक छिपा हुआ कमरा है।

पालघर जिले में बंदरगाह का रास्ता साफ; 76,200 करोड़ के प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी

पालघर: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पालघर जिले में नए बारामाही बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दे दी. 76,200 करोड़ रुपये की इस परियोजना से अगले 10 वर्षों में 12 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हुई पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है.

बंदरगाह विस्तार परियोजना जवाहरलाल नेहरू फॉल अथॉरिटी (जेएनपीए) की 74 प्रतिशत भागीदारी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (एमएमबी) की 26 प्रतिशत भागीदारी के साथ स्थापित की जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 1000 मीटर लंबाई के नौ कंटेनर टर्मिनल, प्रत्येक में चार

बहुउद्देश्यीय बर्थ और तरल कार्गो को संभालने के लिए बर्थ के साथ-साथ तट रक्षक, रोरो के लिए अलग बर्थ का निर्माण किया जाएगा। सेवा और समुद्री संचालन। इसके अलावा बैठक की टिप्पणियों में बताया गया है कि बंदरगाह को जोड़ने वाली सड़कों, अलग रेलवे की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 18 अप्रैल 2024 को दहानू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 31 जुलाई 2023 द्वारा विस्तार बंदरगाह के निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इससे पहले 19 जनवरी, 2024 को केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने पर्यावरणीय जन सुनवाई के बाद बंदरगाह को मंजूरी दे दी थी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण सार्वजनिक निवेश बोर्ड की मंजूरी मिलने तक केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लंबित रही। मोदी के नेतृत्व में रालोआ सरकार के उद्घाटन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट की बैठक में खरीफ सीजन के लिए चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 117 रुपये बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया गया।

प्रस्तावित बंदरगाह की विशेषताएं

- प्राकृतिक गहराई 18 से 20 मीटर
- 24,000 कंटेनर क्षमता से बड़े जहाजों को लंगर डालने में सक्षम
- यह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक बन जाएगा
- सिंगापुर, कोलंबो और अन्य अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों पर निर्भरता खत्म
- स्वच्छ कार्गो (ग्रीन कार्गो) के संचालन हेतु योजना बनाना।

मुंबई में 306 लॉटरी विजेताओं की नींद उडी; घरों की कीमतें बढ़ाने का प्रस्ताव

मुंबई : करीब आठ साल से अपने घर का इंतजार कर रहे 306 लॉटरी विजेताओं को बीते कुछ दिनों से रातों को नींद नहीं आ रही है। विजेताओं की नींद उड़ने का कारण महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) के मुंबई मंडल का 2016 में जारी की गई लॉटरी में शामिल घरों की कीमत में कीमत में इजाफा करने का प्रस्ताव है। निर्माण कार्य में हुए खर्च की वसूली के लिए म्हाडा घरों की कीमत में करीब 7 से 10 लाख रुपये की वृद्धि करने का विचार कर रही है। यह प्रस्ताव जल्द ही म्हाडा उपाध्यक्ष के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। गोरेगांव के पत्रावाला प्रॉजेक्ट के करीब 306 घरों की लॉटरी 2016 में जारी की गई थी। लेकिन बिल्डर द्वारा समय पर प्रॉजेक्ट को पूरा नहीं कर पाने के कारण लॉटरी विजेताओं को अब तक घरों का पजेशन नहीं मिल पाया है। विजेताओं के विरोध को देखते हुए म्हाडा ने खुद प्रॉजेक्ट को पूरा करने निर्णय लिया। मौजूदा समय में बिल्डिंग का निर्माण कार्य करीब पूरा हो चुका है। ऐसे में म्हाडा निर्माण कार्य में हुए खर्च की वसूली के लिए घरों की कीमत में वृद्धि करने की योजना पर काम कर रही है। म्हाडा के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, योजना के आरंभ में प्रॉजेक्ट को निजी बिल्डर को पूरा करना था, उस समय

'हमारे साथ अन्याय'

लॉटरी विजेताओं ने घरों की कीमत में वृद्धि करने के म्हाडा के प्रस्ताव का विरोध किया है। विजेताओं के अनुसार, पिछले आठ साल से इंतजार करने के बावजूद अब तक हमें घर नहीं मिल पाए हैं, वहीं अब घरों की कीमत में वृद्धि कर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। एक लॉटरी विजेता के अनुसार, उनके रिटायरमेंट में अब केवल चार साल बचे हैं और पुराने दर के हिसाब से ही बैंक से लोन प्राप्त करना उनके लिए मुश्किल होगा। ऐसे में और पैसे का इंतजाम करना और मुश्किल होगा। जीवन भर किराए के घर में रहा, जीवन के अंतिम पड़ाव में घर का किराया नहीं भरना होगा, यह सोच कर म्हाडा की लॉटरी में शामिल हुआ था। लेकिन अब लगता है कि जीवन भर किराये के ही घर में रहना होगा।

इस आधार पर लॉटरी में शामिल घरों की कीमत तय की गई थी, लेकिन अधूरा कार्य को पूरा करने में मंडल के काफी पैसे खर्च हुए हैं। इस वजह से घरों की कीमत में बढ़ोतरी करने का विचार किया जा रहा है। जल्द ही कोई निर्णय लेकर घर की नई कीमत जारी की जाएगी।

'अब लोन मिलने में होगी दिक्कत'

लॉटरी विजेता विजय नाईक के अनुसार, घरों की अधिक कीमत हमें मंजूर नहीं होगी। बिल्डर अगर समय पर काम नहीं कर पाए तो उस से पैसे की वसूली करनी चाहिए, ना कि लॉटरी विजेताओं से। अगर समय पर घर मिल गया होता, तो अब तक बैंक लोन की रकम खत्म होने का समय आ गया होता। प्रॉजेक्ट में देरी के कारण बहुत से लोगों को लोन हासिल करने में दिक्कत होगी।

छत ढहने से नौ बच्चे घायल, दो की हालत गंभीर

ठाणे : ठाणे शहर में एक इमारत की छत गिरने से नौ बच्चे घायल हो गए जिनमें से दो की हालत गंभीर

बताई जाती है। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात भारी बारिश के बीच तब हुई जब बच्चे पास के गवांड बाग मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। उन्होंने कहा, घटना में घायल हुए छह बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। स्थानीय विधायक प्रताप सरनाईक ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि बच्चों के समुचित उपचार के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com